चाय और कॉफी की कीमतों को लेकर एक ट्वीट

सुना है पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने चेन्नई एयरपोर्ट पर चाय और कॉफी की कीमतों को लेकर एक ट्वीट किया जिसमे उन्होंने कहा, 135 रुपए की चाय और 180 रुपए की कॉफी की कीमतें सुनकर डर गया हूं।

दरअसल चिदम्बरम साहब को संसद भवन की कैंटीन की कॉफी चाय की आदत पड़ गयी हैं जहाँ उन्हें आज भी चाय कॉफी मात्र 3 रु 15 पैसे में मिल रही है तो उनका चौकना ओर %डरना% तो स्वाभाविक है।

वैसे संसद में चाय कॉफी के रेट सुनकर आप भी मत चौकिए आपको कटिंग चाय अब भी 5 रु से कम नही पड़ रही होगी पर संसद की चाय के 3 रु 15 पैसे रेट जीएसटी लगने के बाद ही है।

सांसदों की खाने की थाली पर भी निगाह आप मार ही लीजिए-

दाल - 5 रुपए 25 पैसे
रोटी - 2 रुपए 10 पैसे
सलाद - 5 रुपए 25 पैसे
दाल चावल -25 रुपए 25 पैसे
मटन बिरयानी - 80 रुपए
चिकन करी - 32 रुपए 60 पैसे

ये रेट जनता के लिए नही है जनता के सेवको के लिए है जिसकी मासिक पगार डेढ़ लाख रुपये से कम नहीं है। उन्हें अन्य सुविधाएं भी इतनी अधिक मिलती है जितनी हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे ओर आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे इसलिए रहने देते हैं।

वैसे हमारे मित्र चन्द्रशेखर गौर जी की संसद भवन में डाली गयी आरटीआई से यह भी पता चला हैं कि संसद में बीते पांच सालों में इन सांसदों के सस्ते भोजन पर 73 करोड़ 85 लाख 62 हजार 474 रुपये बतौर सब्सिडी दी गई।

पहले ये कहा गया था कि 2016 से सब्सिडी देना बन्द कर दी गयी है पर नवीनतम जानकारी से यह पता चला हैं कि अभी भी लगभग 15 करोड़ रु प्रति साल की दर से सांसदों को सस्ते भोजन के सब्सिडी दी जा रही है।

आप बस अब यह याद कर लीजिए कि हमारे मोदीजी रसोई गैस पे सब्सिडी छोड़ने की अपील करते हुए कितने भले लगते हैं ? और रेलवे के टिकट की नीचे की लाईन में क्या लिखा रहता है?

- साइबर नजर

भारत के बैंकिंग इतिहास में अभूतपूर्व स्थिति

भारत के बैंकिंग इतिहास में अभूतपूर्व स्थिति है, एक बैंक दूसरे बैंक को दीवालिया घोषित करने को आमादा है और वित्त मंत्रालय कह रहा है कि 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था दोगुनी हो जाएगी, यानी वित्त मंत्रालय को 7 साल बाद होनी वाली दोगुनी अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल करने में ज्यादा रुचि है और सिर्फ 5 दिन बाद दीवालिया घोषित होने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे सबसे बढ़े बैंक पीएनबी की कोई फिक्र नही है।

हमे लग रहा है कि हम शेक्सपियर के मशहूर ड्रामे कॉमेडी ऑफ एरर्स का नया संस्करण देख रहे हैं।

जिस दिन यह पीएनबी घोटाला सामने आया था वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग में संयुक्त सचिव लोक रंजन ने कहा था यह एक बड़ा मामला नहीं है और ऐसी स्थिति नहीं है जिसे कहा जाए कि हालात काबू में नहीं है आज जब हालात काबू करने की बात आयी है तो एक नया शगूफा उछाल दिया गया है।

आप शुरुआत से देखिए इस मामले से अब तक कैसे निपटा गया है. सबसे पहले अरुण जेटली जी बोले कि इस महाघोटाले के लिए रेग्युलेटर्स-ऑडिटर्स की अपर्याप्त निगरानी और ढीले बैंक प्रबंधन जिम्मेदार है रेग्युलेटर्स ही नियम तय करते हैं और उन्हें तीसरी आंख हमेशा खुली रखनी चाहिए, फिर वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने इस बारे में आरबीआइ को पत्र लिख कर पूछा कि आखिर इतना बड़ा मामला किस तरह से उनकी नजर से बचा रह गया किन वजहों से यह गड़बड़ी हुई है, आपने क्या समीक्षा की ? निगरानी तंत्र क्यो फेल हुआ ?

फिर बीच मे पीएनबी का वर्जन सामने आया जिसे दबा दिया गया, वित्त मंत्रालय को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में पीएनबी ने कहा कि पिछले नौ वर्षों से आडिट नहीं हुआ जिससे यह घोटाला सामने नहीं आ सका। पीएनबी ने अपनी रिपोर्ट में आरबीआइ सहित आडिट एवं नियामक अधिकारियों की चूक की बात कही जिससे जालसाजी बेरोकटोक जारी रही। पीएनबी ने बताया कि पिछला आडिट 31 मार्च 2009 को किया गया था जबकि नियमानुसार आरबीआइ के लिए अनुसूचित बैंकों का हर साल आडिट करना अनिवार्य है। फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर कथा पुराणों की भाषा मे जवाब देने लगे कि आरबीआई के पास पंजाब नेशनल बैंक जैसे घोटालों को रोकने और उनसे निपटने के पर्याप्त अधिकार नहीं हैं और इसलिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित नहीं कर सकते, कहते-कहते वे पीएनबी घोटाले को लेकर यहां तक कह गए, मैं आज यह बताने जा रहा हूं कि आरबीआई में हमें भी बैंकिंग क्षेत्र की धोखाधड़ी और अनियिमितताओं को लेकर गुस्सा आता है और हम आहत और दर्द महसूस करते हैं। यह कुछ कारोबारियों और बैंकों की मिलीभगत से देश के भविष्य को लूटने का काम है।

आपने कभी सर्कस देखा है कभी कोई जिमनास्ट कलाबाजियां खाते हुए रिंग में आता है, कभी कोई लड़की रीछ के मुँह को रस्सी से बांधकर लाती है, कभी कोई जगलर गेंद उछालते हुए चक्कर लगाता है, कभी कोई जोकर हँसते हुए रोने का नाटक करता है, किन बंदरों के हाथ मे उस्तरा सौप दिया है हम लोगो ने ?

- साइबर नजर

डाक से मजदूर मोर्चा मंगवाने वाले पाठकों से अनुरोध

डाक द्वारा मजदूर मोर्चा प्राप्त करने वाले स्थानीय पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी प्रति प्राप्त करने के लिए अपने हॉकर से सम्पर्क करें, क्योंकि 12 फरवरी से साप्ताहिक होने केपश्चात- अखबार को डाक द्वारा भेजना संभव नहीं हो पा रहा है।

अब शिक्षा व्यापार में भी उतरे मंत्री गूजर

पेज एक का शेष

को ध्यान में रखते हुए गूजर जी ने शिक्षा व्यापार में हाथ अजमाना ही बेहतर समझा है। यह स्थाई रूप से चलने वाला साफ़-सुथरा कमाऊ धंधा है।

मुख्यमंत्री खट्टर ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि फ़रीदाबाद की 14 लाख की आबादी की वृद्धि दर 2 प्रतिशत के हिसाब से 28000 बच्चे हर साल पैदा होते हैं तथा 2031 में संभावित आबादी 38 लाख होने के बाद इसी वृद्धि दर से 76000 नये बच्चे हर वर्ष पढने को आयेंगे। इस लिये, इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को पढाने के लिये सरकारी स्कूलों के साथ-साथ प्राइवेट स्कूलो की भी सख्त जरूरत है। लेकिन खट्टर जी ने यह नहीं बताया कि इतनी बड़ी आबादी के लिये उनकी सरकार कितने स्कूल खोलने वाली है ?

उपलब्ध जनकारी के अनुसार नहर पार के तमाम सेक्टरों में से किसी में भी कोई सरकारी स्कूल नहीं खोला गया है और न ही इसके लिये कोई प्रावधान है। सभी सेक्टरों में महंगे प्राइवेट स्कूल हैं। इनमें 3000 से लेकर 10000 रुपये मासिक तक की फ़ीस है। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन 11000 मासिक कमाने वाला ग़रीब अपने बच्चों को कौन से स्कूल मं पढायेगा ?

नये स्कूल खोलने की तो सरकार से कोई अपेक्षा की भी नहीं जा सकती क्योंकि वर्ष 2018-19 में खट्टर सरकार 1000 के करीब स्कूल बंद करने जा रही है। बंद करने का कारण यह बताया जा रहा है कि उनमें पढने वाले बच्चों की संख्या कम है। सर्वविदित है कि जिस स्कूल में कोई पढाने वाला ही न हो, पीने का पानी व शौचालय तक न हो वहां कोई अपने बच्चों को समय बर्बाद करने क्यों भेजेगा ? खट्टर सरकार की यदि यही नीति रही तो धीरे-धीरे सारे सरकारी स्कूल बंद किये जा सकेंगे। ऐसे में फ़िर कृष्णपालों के शिक्षण शोरूम जनता को जी भर के लूट सकेंगे।

सरकारी हैलिकॉप्टर से आये खट्टर

इस शिक्षा दुकान के उद्घाटन के लिये मुख्यमंत्री खट्टर सरकारी हैलिकॉप्टर से पहुंचे। कहने की जरूरत नहीं जनता के खून पसीने की कमाई से चलता है यह हैलिकॉप्टर। इस निजी यात्रा को सरकारी बनाने के लिये खट्टर ने पास के ही गांव खेड़ी में सीएचसी यानी कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर के निरीक्षण का भी दिखावा कर दिया। खट्टर को खूब पता है कि न तो उनके किसी अस्पताल में, न किसी डिस्पेंसरी व हैल्थ सेंटर में पर्याप्त स्टाफ़ है न उपकरण व दवायें आदि। परन्तु अपने इस निजी दौरे को सरकारी रूप देने के लिये निरीक्षण का ड्रामा किया था।

कृष्णपाल के स्कूल को जाने वाली सड़क इतनी बेहतरीन बनी हुई है कि पूरे फ़रीदाबाद में इतनी चिकनी कोई सड़क नहीं। इसी को तो कहते हैं सत्ता का प्रताप। इसी प्रताप के चलते कृष्णपाल ने बरसों पहले क्षेत्र के मास्टर प्लान का पता लगा कर उक्त 8 एकड़ के अलावा और भी काफ़ी ज़मीन किसानों से कौड़ियों के भाव खरीद रखी थी जो आज 3-4 करोड़ प्रति एकड़ से कम की नहीं।

मैं नरेंद्र मोदी आपका डेटा अमेरिकी कंपनियों को दे रहा हूं

पेज एक का शेष

राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया है, हाय, मेरा नाम नरेंद्र मोदी है। मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। जब आप मेरे आधिकारिक एप (नमो) को साइन करते हैं तो मैं आपसे जुड़ी सभी जानकारी अपने दोस्तों यानी अमेरिकी कंपनी को दे देता हूं।

गौरतलब है कि नमो एप डाटा चोरी कांड का खुलासा होने के बाद तब चर्चा में आया है जब कुछ दिन पहले एनसीसी के तकरीबन 13 लाख कैडेट्स को प्रधानमंत्री से बातचीत करने से पहले इसे डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया था। नमो एप के विरोध में 23 मार्च को DeleteNamoApp कैंपेन के तहत दिनभर ट्वीटर पर यह ट्रेंड करता रहा। कांग्रेस का कहना है कि नमो ऐप का इस्तेमाल करने वाले लोगों की निजी जानकारियां उनकी मंजूरी के बिना अमेरिकी कंपनी तक पहुंचाई जा रही हैं।

राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट को बतौर फैक्ट बताते हुए कहा कि एक फ्रांसीसी निगरानी हैकर ने अपने श्रृंखलाबद्ध ट्वीटों में आरोप लगाया है कि नमो एप के उपभोक्ताओं की ईमेल आईडी, तस्वीरें, लिंग व नाम सहित प्राइवेट डाटा उनकी सहमति के बिना एक तीसरे पक्ष के डोमेन पर ट्रांसफर की जा रही हैं।

हालांकि राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद भाजपा ने इसके विरोध में पूरा ट्वीटरवार शुरू कर दिया है। अपना बचाव करते हुए तर्क गढ़े जा रहे हैं कि नमो एप से डाटा चोरी का आरोप लगाकर राहुल गांधी लोगों का ध्यान कैंब्रिज एनालिटिका डाटा चोरी मामले से भटकाना चाहते हैं, नमो एप से कोई भी जानकारी विदेशों में शेयर नहीं की जा रही है।

फेसबुक डाटा लीक कांड का खुलासा होने के बाद राजनीतिक दलों खासकर भाजपा द्वारा चुनाव जीतने के लिए इसका इस्तेमाल करने का भी खुलासा हुआ है। जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जिताने के लिए फेसबुक के माध्यम से कैंब्रिज एनालिटिका ने विभिन्न एप्स का इस्तेमाल कर डटा चोरी किया था उसी तरह भारत में भी भाजपा ने भी चुनाव जीतने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल किया था। हालांकि कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल भी हाल में डाटाचोर कंपनी कैंब्रिज एनालिटिका के ग्राहक बने थे।

मोदी की पार्टी भाजपा 2014 लोकसभा चुनाव के पहले से कुख्यात डाटाचोर कंपनी कैंब्रिज एनालिटिका की चुनाव जीतने के लिए मदद ले रही है। मोदी के कानून मंत्री ने डाटा चोरी के मसले पर जैसे ही प्रेस कांफ्रेंस की उसके घंटे भर बाद ही कैंब्रिज एनालिटिका का एकाउंट भारतीयों को दिखना बंद हो गया और साइट डिलीट दिखाई देने लगी। जाहिर है मंत्री जी को इसकी सूचना पहुंच गयी होगी कि रविशंकर सर, इस हम्माम में हम सब नंगे हैं।

गौरतलब है कि इस प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि इसका इस्तेमाल कर कांग्रेस 2019 का चुनाव एकतरफा करना चाहती है। यह बात समझ से परे है कि जब कांग्रेस ने हाल ही में कैंब्रिज एनालिटिका की सेवाएं लेना शुरू किया था तो यह सवाल क्यों। या फिर भाजपा ने 2014 का चुनाव इसी के बल पर जीता था, जो कांग्रेस के इसकी सेवा लेने की भनक लगते ही खुलासा कर दिया गया कि कहीं 2019 के चुनाव में भाजपा को कड़ी शिकस्त न मिले।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें:

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5
2. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
3. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
4. 5 ई-18 नरेन्द्र बुक सेन्टर - 9810229192
5. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
6. राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
7. हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
8. जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207
9. सिंगला मेडिकल स्टोर, जवाहर कॉलोनी, डिस्पोजल चौक
10. आरसीएम स्टोर, बाबा बालकनाथ मंदिर वाली गली, जवाहर कालोनी, फ़रीदाबाद